Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 30-11-2006

Participants : Gill Shri Atma Singh

an>

Title: Need to bring transparency in the working of Social Welfare Boards of States.

श्री आत्मा सिंह गिल (सिरसा) : महोदय, केन्द्र सरकार करोड़ों रूपये समाज के प्रत्येक वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थन के लिए मंत्रालयों के माध्यम से अलग अलग संस्थाओं एवं संस्थानों द्वारा आबंटित करती हैं और इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समाज सेवी संस्थाओं को अनुदान के रूप में देती है ताकि इन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल सके। महिला एवं बाल ि वकास मंत्रालय ने अंतगत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड भी महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए अपने राज्य समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान राशि आबंटित करती है। अनेकों संस्थाएं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करती हैं। इन संस्थाओं को आवेदन करने के लिए समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। राज्य समाज कल्याण बोर्डो में बहुत अनियमितताएं हैं। अतः इन संस्थानों में पारदर्शिता लाने हेतु आवश्यक प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सभी लोगों को केन्द्र सरकार की योजनाओं से पर्याप्त लाभ मिल सके।